राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 6 अंक 192

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, बुधवार, 21 दिसंबर, 2022

www.jagran.com

पृष्ठ 14

भाजपा अध्यक्ष नड्डा के कार्यकाल को मिल सकता है विस्तार

>> 4

जागरण विशेष

सुशिक्षित समाज को 'ग्रीन सिग्नल' दे रहा यह स्कूल

नई दिल्ली : देश में छह से 14 वर्ष के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके प्रयास भी होते हैं, लेकिन गुजरात में एक अनूठी सरकारी पहल अनुकरणीय उदाहरण बनकर सामने आई है। (पेज-7)

संपादकीय

समीक्षा की मांग करती शराबबंदी: नशाखोरी एक बुराई है, किंतु इसका समाधान सुशिक्षा और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने में है, न कि शराबबंदी जैसी नीति बनाने में। शंकर शरण का दृष्टिकोण।

पंथ प्रचार की मनमानी स्वतंत्रता: किसी को यह कहने की आजादी क्यों होनी चाहिए कि अन्य तरीके से उपासना करने वाले हीन और हेय हैं? राजीव सचान का आलेख।

● पेज 8

विमर्श

आरएसएस और स्वतंत्रता आंदोलन: कांग्रेसी नेताओं के संघर्ष से ही हमें आजादी नहीं मिली। इसके लिए अन्य असंख्य लोगों ने भी खून बहाया। राम माधव का आलेख।

कोलेजियम पर हो पुनर्विचार : अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का विकास हो तो हमें न्यायिक नियुक्ति की पारदर्शी व्यवस्था पर निश्चित रूप से विचार करना होगा। डा. वरुण छाबर का विश्लेषण। ● पेज-9

सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

जीवंत शरद : शतम्

स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियां

● पेज 13

'कोरोना पाजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करें राज्य'

नई दिल्ली : कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने देश में डेसकी रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यों से सभी कोरोना पाजिटिव सैंपल की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा गया है ताकि नए वैरिएंट पर नजर रखी जा सके। जापान, ब्राजील, चीन तथा अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को समीक्षा बैठक भी करेंगे। (पेज-3)

बीमार व वृद्ध गवाह के पास नीचे उतरकर आया कोर्ट

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में मंगलवार को अनोखी गवाही हुई। एक बीमार वृद्धगवाह के लिए तीसरी मंजिल से उतरकर कोर्ट निचले तल पर आया। फारियादी के गवाह के पास पहुंचकर न्यायालयीन कार्यवाही हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 के कोर्ट का यह मानवीय पहलू तब सामने आया, जब गैरइरादतन हत्या मामले में 75 वर्षीय वृद्ध रामनरेश सिंह गवाही देने न्यायालय पहुंचे। (पेज-5)

खरगे के बयान पर संसद में जमकर हंगामा

दोनों सदनों में तीखी नोकझोंक, भाजपा सदस्यों ने की माफी की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद में अमूमन विपक्ष ही अपनी मांगों को लेकर हंगामा और नारेबाजी करता दिखता है, लेकिन मंगलवार को संसद के दोनों सदनों का नजारा अलग था। जहां सत्ता पक्ष के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे। मुद्दा था कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के अलवर में दिए उस विवादित बयान का जिसमें उन्होंने कहा था, 'देश को आजादी दिलाने में उनकी पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी दी, लेकिन भाजपा वालों के घर का तो कुत्ता भी नहीं मरा।' भाजपा सरकार बात तो शेर की तरह करती है, लेकिन काम चूहे की तरह करती है।'

भाजपा सदस्यों ने दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही खरगे के इस बयान को अभद्र बताते हुए माफी मांगने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही करीब आधे घंटे तक स्थगित रही, जबकि राज्यसभा में काफी देर तक कामकाज नहीं हो पाया। खरगे ने कहा कि उन्होंने यह बयान सदन से बाहर दिया है, लेकिन उस पर वह अभी भी कायम हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'वे कांग्रेस पर 'भारत तोड़ो यात्रा' निकालने का आरोप लगाते हैं, जिस पर मैंने यह कहकर जवाब दिया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए जान न्योछावर की थी। आपकी तरफ से (भाजपा) किसने जीवन बलिदान दिया है।'

सुरजेवाला ने किया खरगे का बचाव पेज>>3

स्थगित करनी पड़ी लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा में भी अवरोध

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बोले, मैं अपने बयान पर अभी भी कायम

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 'कुत्ते' वाले बयान को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में जब खरगे और पीयूष गोयल के बीच तीखी बहस हुई, तो सभापति जगदीप धनखड़ स्थिति को संभालते दिखे। एएनआइ

एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है कांग्रेस : पीयूष गोयल

राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने भी कहा कि यह आजादी के आंदोलन में शामिल कांग्रेस नहीं है, बल्कि यह एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है। यह भटकी हुई कांग्रेस है। उन्होंने खरगे से माफी मांगने की मांग की और कहा कि शायद उन्हें इतिहास याद नहीं है। कांग्रेस की वजह से जम्मू-कश्मीर की क्या हालत हुई। कैसे पाक ने भारत के हिस्से पर कब्जा करके रखा है। इन्हीं के समय चीन ने भारत की जमीन हड़प ली थी। इन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया।

धनखड़ बोले- यह जो हो रहा है, वह दुखद है

राज्यसभा में जब स्थिति बिगड़ने लगी तो सभापति जगदीप धनखड़ ने गोयल को अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही विपक्ष को भी फटकार लगाई। धनखड़ ने कहा कि यह जो हो रहा है, वह दुखद है। देश की 130 करोड़ जनता हमें देख रही है। वह हम पर हंस रही है। क्या स्थिति बन गई है। हम एक-दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद हंगामा थोड़ा थमा। धनखड़ ने यह भी कहा, नियम-267 के तहत वह दैनिक आधार पर सदन का कामकाज स्थगित करने से नहीं हिचकेंगे। मेरिट के आधार पर ही कोई फैसला लेंगे।

आजादी की लड़ाई में शामिल कांग्रेस दूसरी थी : प्रल्हाद जोशी

इस मुद्दे पर लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और कहा कि यह नकली कांग्रेस है। हम सभी को पता है कि इसने सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और सरदार पटेल के साथ कैसा सुलूक किया जो असली कांग्रेस में थे। आजादी की लड़ाई में शामिल कांग्रेस यह नहीं है। न ही यह महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कांग्रेस है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। यह इतालवी कांग्रेस है जिसको कुछ अन्य लोग चला रहे हैं, वह रबड़ स्टाम्प अध्यक्ष हैं। उन्होंने वीर सावरकर और स्मृति इरानी के लिए भी ऐसी बातें कही हैं।

घुसपैठ के लिए चीन के राजदूत को तलब क्यों नहीं किया : कांग्रेस

नई दिल्ली : चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस ने राजग सरकार की चीन नीति पर सवालों के तीर दागे। चीन से रिश्ते सामान्य नहीं होने के विदेश मंत्री के बयान पर कहा कि ऐसा है तो पाक की तरह चीनी राजदूत को अब तक क्यों नहीं तलब किया गया। (पेज-3)

गिलानी के मकान समेत जमात की 10 करोड़ की संपत्ति सील

श्रीनगर : कश्मीर में जिहादीभर अलगाववादी और पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहने वाले दिवंगत कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के मकान और प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी दो संपत्तियों को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई आतंकी और उनके वित्तीय ढांचे को नष्ट करने के लिए प्रदेश जांच एजेंसी (एसआइए) की सिफारिश पर की गई है। सील की गई संपत्तियों की कीमत 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। (पेज-6)

उत्तर प्रदेश में कोहरे ने थामा बसों का पहिया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से परिवहन निगम की बसों का पहिया थमने जा रहा है। कोहरा होने पर रात आठ बजे से बसों का संचालन रोकने का सख्त निर्देश है। ऐसे में अगले दिन सुबह आठ बजे या कोहरा छंटने के बादही बसें गंतव्य की ओर जाएंगी। लगभग एक माह तक कोहरे को देखते हुए बसों की आनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर मंगलवार को परिवहन निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। (पेज-7)

कश्मीरी हिंदू के हत्यारे सहित तीन आतंकी ढेर

शोपियां में मंगलवार को आतंकियों के विरुद्ध अभियान के दौरान मुस्तैद सुरक्षा बल। एएनआइ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- शोपियां में हुई मुठभेड़, द रजिस्टेंस फ्रंट के थे मारे गए तीनों आतंकी
- दो आतंकी कश्मीरी हिंदू पूर्ण कृष्ण भट्ट और नेपाली नागरिक की हत्या में थे लिप्त

सुरक्षाबलों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के तीन आतंकियों को मार गिराया। इनमें से दो आतंकी कश्मीरी हिंदू पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या और एक नेपाली नागरिक की हत्या में लिप्त थे। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार व अन्य साजोसामान भी मिला है। कश्मीरी हिंदू पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या 13 अक्टूबर को शोपियां के चौधरीगुंड में उनके घर के बाहर कर दी गई थी। वहीं, नेपाली नागरिक तिल बहादुर समेत दो श्रमिक पिछले माह नवंबर के पहले सप्ताह में अनंतनाग में एक स्कूल परिसर के बाहर आतंकी हमले में घायल हुए थे। बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान तिल बहादुर की मौत हो गई थी।

जानकारी के अनुसार पुलिस को सोमवार देर रात पता चला कि हथियारों से लैस तीन आतंकी शोपियां के मुंजमर्ग में अपने किसी संपर्क सूत्र से मिलने आए हैं। पुलिस ने उसी समय सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। आधी रात के बाद जवानों ने गांव की घेराबंदी करते हुए आने-जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद मंगलवार तड़के सुरक्षाबलों ने अपना तलाशी अभियान शुरू किया। सुबह जब तलाशी लेते हुए जवान आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने आतंकियों को कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी जारी रखी। सुबह करीब साढ़े पांच बजे शुरू हुई मुठभेड़ लगभग दो घंटे चली। बाद में गोलियों से छलनी तीन आतंकियों के शव मिले। मारे गए आतंकियों में से दो की पहचान समीर लोन निवासी शोपियां और उमर नजीर निवासी अनंतनाग के रूप में हुई है। तीसरा आतंकी दानिश था, जो उत्तरी कश्मीर में ओल्ड टाउन (बारामुला) का रहने वाला था।

हिंदुओं की हत्याओं में शामिल सिर्फ एक आतंकी ही जिंदा बचा

कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हिंदुओं और अन्य राज्यों के श्रमिकों की हत्या व उन पर हमलों की विभिन्न वारदात में लिप्त लगभग सभी आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें शोपियां का लतीफ और अनंतनाग का उमर नजीर भी शामिल है। अल्पसंख्यकों की हत्याओं में शामिल अब सिर्फ एक ही आतंकी आदिल वानी जिंदा बचा है। वह भी जल्द मारा जाएगा।

50 साल पुराने सभी पुलों का आडिट कराने का निर्देश

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने पुलों के ढहने की घटनाओं को देखते हुए 50 साल पुराने सभी पुलों का आडिट करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी एजेंसियों-एनएचएआइ और एनएचआइडीसीएल से कहा है कि जिन पुलों में कमी पाई जाती है, उनमें बिना किसी देरी के मरम्मत का कार्य किया जाए। हर महीने की 10 तारीख को उसकी रिपोर्ट भी तलब की है। (पेज-7)

यूएनएससी के विस्तार की प्रबल संभावना : गुटेरस

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावना पर अब 'गंभीरता से विचार' किया जा रहा है। अब यह सदस्य देशों का मामला है और इन वार्ताओं में सचिवालय का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सितंबर में हमारे महासभा सत्र के दौरान मैंने पहली बार अमेरिका और रूस से स्पष्ट रूप से यह संकेत सुना कि वे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के पक्ष में है। (पेज-11)

तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने की थी कोल्हे की हत्या

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- 11 लोगों को एनआइए के आरोपपत्र में बनाया गया है आरोपित
- इरफान खान नामक एक व्यवसायी है हत्याकांड का मास्टरमाइंड

एनआइए ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि इस वर्ष 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती में दवा व्यवसायी उमेश कोल्हे की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने की थी। आरोपपत्र में एनआइए ने कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया है। सभी आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

उमेश कोल्हे ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी की थी। इसके बाद दुकान से घर जाते हुए रात के समय उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या के समय उमेश के पुत्र संकेत एवं पत्नी वैष्णवी भी दूसरी बाइक से उनके पीछे ही आ रहे थे। एनआइए ने इस मामले में विशेष कोर्ट में पेश आरोपपत्र में कहा है कि आरोपित युसुफ खान ने उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश रची और अन्य आरोपितों के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया।

एनआइए को इस मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें आरोपित उमेश कोल्हे को बाइक पर भागते दिखाई दे रहे हैं। एनआइए का दावा है कि हत्या की साजिश में शामिल सभी आरोपित तबलीगी जमात के सदस्य हैं। एनआइए ने विशेष कोर्ट में यह आरोपपत्र 16 दिसंबर को पेश किया। आरोपपत्र में इरफान खान नामक एक व्यवसायी को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया है।

नूपुर शर्मा के समर्थन में वाट्सएप संदेश फारवर्ड करने से थी नाराजगी

एनआइए ने आरोपपत्र में कहा है कि उमेश कोल्हे से आरोपितों का कोई विवाद नहीं था। उमेश कोल्हे कानून का पालन करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आरोपितों ने इंटरनेट मीडिया पर उमेश कोल्हे द्वारा नूपुर शर्मा के समर्थन में कोई संदेश किसी वाट्सएप ग्रुप में फारवर्ड किया था। इस कारण इरफान एवं उसके साथियों ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। आरोपपत्र के अनुसार, इस हत्याकांड के कारण समाज में भय देखा गया। कई जगह सांप्रदायिक तनाव एवं दंगे भी होते देखे गए। बता दें कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही राजस्थान के उदयपुर में भी एक दर्जी की इसी प्रकार गला काट कर हत्या कर दी गई थी।

उमेश कोल्हे। (फाइल फोटो)। एएनआइ

आरोपपत्र में कहा गया है कि यह हत्या कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि इस्लामी कट्टरपंथ के तहत किया गया एक सोचा-समझा अपराध था। इस घटना का मास्टरमाइंड इरफान खान जरूरतमंदों की एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने वाले एक स्वयंसेवी संगठन रहबर हेल्पलाइन का अध्यक्ष था। इस कारण वह कई लोगों के संपर्क में था। इस वर्ष मई में नूपुर शर्मा विवाद गर्म होने के बाद इरफान अपने साथियों के साथ अमरावती के एक पुलिस थाने में नूपुर शर्मा के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने पहुंचा था। लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए एफआइआर दर्ज करने से मना कर दिया था कि नूपुर पर दिल्ली सहित कई स्थानों पर पहले ही एफआइआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद इरफान और उसके साथियों ने इंटरनेट मीडिया पर नूपुर का समर्थन करने वालों को सबक सिखाने की योजना बनाई, जिसका शिकार उमेश कोल्हे बना।

दुश्मनों के लिए 'प्रलय' बनेगी राकेट मोटर से संचालित स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल

नई दिल्ली, एएनआइ

सीमा पर चीन से तनातनी के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के हाथ और मजबूत होने वाले हैं। सेना को जल्द ही 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' मिलने की उम्मीद है। रक्षा खरीद के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक में इसी सप्ताह इस मिसाइल को खरीदने के सेना के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

प्रलय सालिड प्रोपेलेंट राकेट मोटर से संचालित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें कई नवीनतम टेक्नोलाजी का प्रयोग किया गया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार दो दिन सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तभी से सेना इसे खरीदने और अपने बेड़े का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। इंटरसेप्टर मिसाइल की चकमा देकर अपने लक्ष्य को भेदना इसकी बड़ी खूबी है। यह हवा में ही कुछ दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदलकर लक्ष्य तक जाने की क्षमता से लैस है। इसकी यही खूबियां सशस्त्र बलों के लिए इसके महत्व को बढ़ाती हैं। यह दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है।

150

से 500 किलोमीटर तक है सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल प्रलय की रेंज

- इसी सप्ताह उच्चस्तरीय बैठक में मिसाइल खरीदने के सेना के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
- हवा में ही मार्ग बदलने और दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है प्रलय

<< सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल 'प्रलय'। (फाइल फोटो)। प्रेट्र

राकेट फोर्स बनाने की तैयारी

प्रलय को सेना में शामिल करने की दिशा में बढ़ रहे कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सेना में एक राकेट फोर्स बनाने की तैयारी है। रक्षा मंत्रालय में उच्चस्तर पर यह विमर्श हो रहा है। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा था कि देश के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत सीमा पर दुश्मनों को चुनौती देने के लिए राकेट फोर्स के गठन की दिशा में काम कर रहे थे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ प्रलय मिसाइलों के मिलने से हमारी सेनाओं के पास सबसे लंबी रेंज तक वार करने में सक्षम टैक्टिकल वीपन सिस्टम तैयार हो जाएगा।

बहुरंगे दिन

कृषि मंत्रालय ने संसद में की 'विशेष मिलेट्स लंच' की मेजबानी, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के स्वागत के लिए मंत्रालय ने अपनाया अनूठा तरीका, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों व सांसदों ने चखे मोटे अनाज के लजीज व्यंजन

गरीब के घर से सांसदों की थाली तक पहुंचे मोटे अनाज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आमतौर पर गरीबों की थाली का भोजन कहे जाने वाले ज्वार, बाजरा, रागी और सावां जैसे मोटे अनाजों के दिन बहुरने लगे हैं। मंगलवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में कृषि मंत्रालय की मेजबानी में 'विशेष मिलेट्स लंच' का आयोजन किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सभी दलों के सांसदों ने मोटे अनाजों से तैयार लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया। 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स (पोषक अनाज) वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। इसी के स्वागत के लिए यह आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, 'प्रधानमंत्री भोजन की थाली में इन पोषक अनाज को पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाना चाहते हैं। इसका सीधा लाभ मिलेट्स की खेती करने वाले छोटे किसानों को मिलेगा।' पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लंच में सभी पार्टियों के लोगों के भाग लेने की सराहना की।

संसद में सुबह ही संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों से लोगों के बीच मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उच्च गुणवत्ता और पोषकतत्वों से भरपूर अनाज हैं। बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि मोटे अनाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं का प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से जिक्र किया। मोदी ने कहा कि जी-20 की विभिन्न बैठकों में आने वाले अतिथियों के भोज में कम से कम एक व्यंजन मोटे अनाज का होना चाहिए। आंगनवाड़ी, स्कूलों के साथ अन्य सरकारी बैठकों के मैन्यू में भी इन अनाजों को शामिल किया जाना चाहिए। पीएम ने इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। कहा कि सांसद भी अपनी तरफ से दिए जाने वाले भोज में इन्हें शामिल करें। मोटे अनाज की खेती करने वाले ज्यादातर छोटी जोत वाले किसान हैं। इनकी खपत बढ़ने से उन किसानों को आर्थिक लाभ होगा।

अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में मंगलवार को नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय द्वारा दोपहर के भोज का आयोजन हुआ। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोस अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मोटे अनाज के व्यंजनों का आनंद लेते दिखे। एएनआइ

व्यंजन तैयार करने कर्नाटक और राजस्थान से आए थेरसोइए पेज>>3

दिल्ली के एलजी ने आप से 97 करोड़ वसूलने के दिए आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी तौर पर प्रकाशित करने का आप पर आरोप
- आप ने आदेश को बताया अवैध, कहा- कानून की नजर में इसका कोई मूल्य नहीं

राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी तौर पर प्रकाशित कराने के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एलजी ने सितंबर, 2016 के बाद के सभी विज्ञापनों की जांच भी कराने के निर्देश देते हुए केजरीवाल सरकार द्वारा गठित सरकारी एजेंसी शब्दार्थ में संविदा या आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों के स्थान पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए कहा है। शब्दार्थ के गठन के बाद से इसका वित्तीय आडिट भी कराया जाएगा।

वहीं, एलजी के आदेश को अवैध बताते हुए आप ने कहा कि उसका कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं है। यह भी कहा कि भाजपा की राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपये खर्च कर दूसरे राज्यों में विज्ञापन छपवाए हैं। एलजी कार्यालय के अनुसार सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति (सीसीआरजीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अगस्त, 2016 के निर्देश पर जांच करने पर पाया था कि ऐसे विज्ञापनों पर 97.14 करोड़ रुपये (97 करोड़, 14 लाख, 69 हजार 137 रुपये) खर्च किए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।

डीआइपी ने किया विज्ञापनों पर खर्च का आकलन पेज>>2

****

366 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा मंगलवार को दिल्ली का। फरीदाबाद का 340, गाजियाबाद का 333, ग्रेटर नोएडा का 392, गुरुग्राम का 364 और नोएडा का 324 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया।

आज का मौसम

आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय घना कोहरा होगा।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
21 दिसंबर	21.0	6.0
22 दिसंबर	21.0	6.0
नोएडा		
21 दिसंबर	24.0	9.0
22 दिसंबर	23.0	9.0
गुरुग्राम		
21 दिसंबर	21.0	10.0
22 दिसंबर	21.0	10.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

चार नाइजीरियाई समेत पांच ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली : "नशा मुक्त भारत अभियान" के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार नाइजीरियाई नागरिक समेत पांच ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.90 लाख की 18 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स और 359 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों के बारे पता लगाने की कोशिश कर रही है। (जासं)

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की 75 किमी प्रति घंटा स्पीड तय

नोएडा : नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन (चार पहिया) वाहनों की स्पीड को 100 से घटाकर 75 किमी प्रतिघंटा किया गया है। भारी वाहनों की लिमिट 80 से घटाकर 60 किमी प्रतिघंटा की गई है। एमपी-1, 2, 3, रोड नंबर-6, डीएससी रोड की स्पीड लिमिट को 80 से घटाकर 60 किमी प्रतिघंटा किया गया है। वहीं एलिवेटेड रोड पर चार पहिया वाहन 50 और भारी वाहन 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगे। यह नियम 15 फरवरी तक लागू रहेगे। (जासं)

डीआइपी ने किया विज्ञापनों पर खर्च का आकलन

प्रथम पृष्ठ से आगे

सीसीआरजीए ने दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआइपी) को ऐसे विज्ञापनों पर खर्च कुल धनराशि का आकलन कर उसे आम आदमी पार्टी से वसूलने के निर्देश दिए थे। डीआइपी ने इसके बाद पता लगाया कि ऐसे विज्ञापनों पर 97.14 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 30 मार्च, 2017 को डीआइपी ने अग्र संयोजक को इसमें से भुगतान किए जा चुके 42.26 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा। साथ ही शेष 54.87 करोड़ रुपये विज्ञापन एजेंसियों/प्रकाशनों को करीब 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन पांच साल आठ महीने बीतने के बाद भी आप ने डीआइपी के आदेश का पालन नहीं किया।

एम्स में नई तकनीक से एडवांस स्टेज के स्तन कैंसर के मरीजों का इलाज

अब तक 100 से ज्यादा मरीजों का रेडियो फार्मास्युटिकल थेरेपी से हो चुका है इलाज

डाक्टर इसे एडवांस स्टेज के मरीजों के लिए मान रहे हैं उम्मीद की एक नई किरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

न्यूक्लियर मेडिसिन के डाक्टर पहले स्तन कैंसर के मरीजों का इलाज नहीं करते थे। सिर्फ पेट-स्कैन जांच कर कैंसर के फैलाव की रिपोर्ट कैंसर विशेषज्ञ को दे दिया करते थे। लेकिन, अब एम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में नई तकनीक रेडियो फार्मास्युटिकल थेरेपी से ट्रायल के रूप में एडवांस स्टेज के स्तन कैंसर की बीमारी से पीड़ित महिला मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। इसके शुरुआती नतीजों में यह बात सामने आई है कि इलाज की यह नई तकनीक एडवांस स्टेज के स्तन कैंसर के मरीजों की उम्र बढ़ाने में मददगार है। इसलिए यह मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण है।

एम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के डाक्टर जर्मनी के यूनिवर्सिटी आफ मेंज के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में इस तकनीक से 69 मरीजों के इलाज पर एक शोध पत्र एम्स के डाक्टर यूरोपियन जर्नल आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मालिक्यूलर इमेजिंग में प्रकाशित कर चुके हैं। एम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डा. सौएस बल ने कहा कि स्तन कैंसर के मरीजों का कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी व रेडियोथेरेपी से इलाज किया जाता है, लेकिन एडवांस स्टेज के मरीजों के इलाज का असरदार विकल्प मौजूद नहीं है। ट्रिपल निगेटिव स्तन कैंसर की बीमारी बेहद खतरनाक होती है। ऐसे मरीजों के इलाज का कोई विकल्प नहीं बचता तो रेडियो फार्मास्युटिकल थेरेपी से इलाज के बारे में सोचा जा सकता है। एम्स में एडवांस स्टेज के स्तन कैंसर की बीमारी से पीड़ित अभी 100 से ज्यादा महिला मरीजों का इलाज हो चुका है। इस तकनीक में मरीज को रेडियोपृथिवित्व दवा दी जाती है, जो कैंसर सेल को टारगेट करके खत्म करती है। सामान्य तौर पर एडवांस स्टेज के स्तन कैंसर की महिला मरीज छह से 10 माह तक बच पाती हैं।

एम्स में शुरू हुई घर बैठे आनलाइन रिपोर्ट हासिल करने की सुविधा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली एम्स में मरीजों की जांच रिपोर्ट आनलाइन उपलब्ध होना शुरू हो गई है। अब पहले की तरह मरीज घर बैठे जांच रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मरीज सुविधा के अनुसार स्मार्ट फोन व लैपटाप या कंप्यूटर पर जांच रिपोर्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले सकते हैं। पुराने मरीजों की जांच रिपोर्ट की ई-फाइल का डाटा भी आनलाइन उपलब्ध हो गया है। एम्स में अब ज्यादातर डिजिटल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को एम्स के सर्वर पर रैनसमवेयर अटैक की घटना हुई थी। इसमें एम्स के ई-हास्पिटल के मुख्य सर्वर सहित पांच दूसरे सर्वर का डाटा हैक कर लिया गया था। इस वजह से एम्स की डिजिटल सेवाएं ठप हो गई थीं। कई दिनों तक अस्पताल में मरीजों का आनलाइन पंजीकरण और जांच के लिए बार कोड तैयार नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से मैनुअल तरीके से इलाज और जांच की सुविधाओं को संचालित किया जा रहा था। ट्रायल के रूप में पांच दिसंबर को ओपीडी का आनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। ओपीडी पंजीकरण की सुविधा सामान्य होने के बाद 12 दिसंबर को आनलाइन अप्वाइंटमेंट की सुविधा शुरू हुई थी। लेकिन, उस वक्त घर बैठे आनलाइन रिपोर्ट लेने की सुविधा शुरू नहीं हो पाई थी।

उपराज्यपाल की मौजूदगी में निलोठी में जलाई जाएगी 2800 किलो ड्रग्स

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

2400 करोड़ है जलाई जाने वाली ड्रग्स की अनुमानित कीमत

2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्रग्स को जलाने की दी थी अनुमति

- पहली बार इतनी बड़ी मात्रा जलाई जाएगी ड्रग्स

वीके सक्सेना। फाइल फोटो

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस बुधवार को निलोठी स्थित एक खाली मैदान में विभिन्न तरह की करीब 2800 किलो ड्रग्स जलाएगी। ये ड्रग्स विभिन्न मामलों में पिछले कई वर्षों में पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। इनकी कीमत 2400 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पुलिस के अनुसार विभिन्न मामलों में पकड़ी जाने वाली ड्रग्स पहले भी जलाई जाती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार जलाई जा रही है।

इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिस ड्रग्स का निस्तारण किया जाएगा, उसे पिछले कई वर्षों में दिल्ली पुलिस की विभिन्न विशेष यूनिट, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इन सभी मामलों का अदालतों से निपटारा होने के बाद इसे नष्ट करने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तस्करों से बरामद ड्रग्स को जलाने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस को ड्रग्स जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, पुलिस उसे अब तक जला नहीं पाई थी।

राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर फिलहाल किसी भी चीज को जलाने पर रोक है। ऐसे में तस्करों से बरामद ड्रग्स दवा कंपनियों को क्यों नहीं बेची जा रही? क्या इसे जलाया जाना ही एक मात्र विकल्प है? इन सवालों के जवाब में पुलिस अधिकारियों का कहना है ड्रग्स इसलिए जलाई जाएगी, ताकि इससे तस्करों को संदेश जाए कि पुलिस उनकी धर पकड़ तेज करेगी। तस्करों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की पालिसी के तहत ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में तस्करों से बरामद हाथी दांतों को भी जला दिया जाता है, जबकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है।

'बच्चों पर यौन उत्पीड़न का हो सकता है दीर्घकालिक खौफनाक प्रभाव'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

16 साल पहले छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में शिक्षक को दिए अनिवार्य सेवानिवृति के दंड को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

छात्रा से यौन उत्पीड़न के 16 वर्ष पुराने मामले में शिक्षक की दिए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों की मानसिक स्थिति पर प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि नाबालिग की मानसिक स्थिति बहुत कोमल होती है। ऐसी घटनाओं के उन पर दीर्घकालिक खौफनाक प्रभाव हो सकते हैं। जिससे कई वर्षों तक उनकी सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

वर्ष 2006 में आरके पुरम क्षेत्र के एक निजी स्कूल की नौवीं कक्षा की छात्रा ने अपने भौतिकी विज्ञान के शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के आदेश पर शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। शिक्षक ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष राहत की मांग करते हुए वर्ष 2012 में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने मई 2022 में दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद शिक्षक ने राहत के लिए दो सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि छात्रा का यौन उत्पीड़न हुआ था। पीठ ने दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखा है।

बगैर भेदभाव सरकारी अस्पतालों को देना चाहिए उपचार : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: लोक नायक अस्पताल में दूसरे राज्यों के मरीजों से भेदभाव होने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मरीज के निवास स्थान की परवाह किए बगैर सरकारी अस्पतालों को सभी को उपचार देना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कहा कि अस्पताल किसी भी नागरिक पर वोटर आइडी के लिए दबाव नहीं बना सकते। दूसरे राज्यों से आए मरीजों को उपचार से वंचित नहीं रख सकते। पीठ ने लोक नायक अस्पताल को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता का एमआरआइ 26 दिसंबर को करे।

बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले गुलाम महबूब ने हाल में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसमें आरोप लगाया था कि लोक नायक अस्पताल में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। घुटने की जांच करने को एमआरआइ के लिए 15 जुलाई 2024 की तारीख दी गई है। यह आरोप भी लगाया कि अस्पताल में निश्शुल्क एमआरआइ की सुविधा केवल दिल्ली के लोगों को दी जा रही है। रेडियो फार्मास्युटिकल थेरेपी से इलाज में यह देखा गया कि बीमारी पूरी तरह ठीक तो नहीं होती, लेकिन 26 माह तक मरीज बचे रहते हैं। जल्द ही इस पर नया शोध पत्र प्रकाशित होने वाला है।

आरबीआइ ने मांगी डिटेल, नहीं मिलेगा अवैध निर्माण पर लोन

सौरभ पांडेय, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की वसुंधरा योजना में अवैध फ्लैटों को खरीदने के लिए अब बैंक लोन नहीं देंगे। अवैध निर्माण रोकने के लिए रिजर्व बैंक आगे आया है। आरबीआइ ने परिषद को पत्र लिखकर सभी अवैध निर्माणों की डिटेल मांगी है। इस डिटेल को आरबीआइ सभी बैंक और एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के साथ साझा करेगा। इसके बाद इन अवैध फ्लैटों पर लोन नहीं होगा और अवैध निर्माण रुक सकेगा।

वसुंधरा के 19 सेक्टरों में कुल करीब एक हजार से अधिक अवैध निर्माण किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर निर्माणों पर नोटिस जारी कर बिल्डरों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है। हालांकि अब इनमें से ज्यादातर अवैध फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। वर्तमान में ही परिषद ने करीब तीन सौ अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि कभी कभार ही कोई लोन लेकर फ्लैट खरीदता है। इसलिए अधिकांश लोग बिल्डर से खरीदते हैं। इसलिए इस पर नया शोध पत्र प्रकाशित होने वाला है।

सख्ती

- अवैध निर्माण पर लगाम कसने के लिए अब रिजर्व बैंक से उम्मीद
- आरबीए ने आरबीआइ को पत्र लिखकर लोन पर रोक की मांग की थी

रिजर्व बैंक को अवैध निर्माणों पर लोन नहीं देने के लिए पत्र लिखा गया था। इसपर जवाब आ गया है। आरबीआइ ने अवैध निर्माणों के संबंध में सभी डिटेल मांगी है। जल्द ही इन्हें मुहैया करवाया जाएगा। इससे अवैध निर्माणों पर पूरी तरह लगाम लग सकेगी। जल्द ही टास्क फोर्स बनाकर वर्तमान में जारी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा।

- रणधीर प्रसाद, आवास आयुक्त

रिजर्व बैंक से लगाई थी गुहार : पिछले दिनों आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने रिजर्व बैंक को पत्र लिखा था। इसमें मांग की गई थी आरबीआइ सभी बैंकों व एनबीएफसी को आदेश दे कि बिना नक्शे की जांच किए किसी भी फ्लैट पर लोन नहीं दे। इसके बाद रिजर्व बैंक ने आवास विकास परिषद से सभी अवैध निर्माणों की डिटेल मांगी है।

नहीं हुए लोन तो बंद होगा अवैध निर्माण : दरअसल, बिल्डर अवैध फ्लैट बनाकर उन्हें सस्ते में बेच देते हैं। जबकि जीडीए अथवा आवास विकास परिषद के फ्लैटों के दाम इन अवैध फ्लैटों से करीब दो गुना अधिक होते हैं। अवैध फ्लैटों पर सरकारी बैंकों के साथ एनबीएफसी भी लोन देते हैं। इसके चलते लोगों के लिए फ्लैट खरीदना आसन हो जाता है। अगर लोन होना बंद हो जाएगा तो इन फ्लैटों के खरीदार ही नहीं मिलेंगे। जीडीए और आवास विकास परिषद के फ्लैट आसानी से बिकने लगेंगे।

एयरपोर्ट पहुंचने पर कहां जाना है, भूल गया यात्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सीआइएसएफ ने की मदद

- तीसरी आंख की मदद से यात्री को ढूंढ लिया गया
- 40 घंटे तक टर्मिनल-3 पर भटकता रहा युवक

भूलने की बीमारी से ग्रस्त एक युवक आइजोल आइ एयरपोर्ट पर पहुंचा और अचानक यह भूल गया कि उसे कहां जाना है। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि गंतव्य भूलने के बाद युवक टर्मिनल-3 पर 40 घंटे इधर-उधर भटकता रहा। बाद में जब उनके माता-पिता ढूंढ़ते-ढूंढ़ते यहां पहुंचे तब सीआइएसएफ कर्मियों की मदद से उन्हें खोज लिया गया। युवक को माता-पिता को सौंप दिया है।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक युवक को आइजोल के लिए उड़ान लेनी थी, लेकिन बोर्डिंग गेट के पास अचानक वे यह भूल गए कि उन्हें कहां जाना है। उधर, उनके माता-पिता ने जब उन्हें फोन किया तो पाया कि युवक का मोबाइल आफ है। इसके बाद उन्होंने स्वजन को फोन कर पता किया कि क्या युवक आइजोल पहुंचा। वहां उन्हें पता चला कि युवक अभी तक आइजोल नहीं पहुंचा है। इसके बाद अपने स्तर पर पूरा पता करने के बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चला तो माता-पिता दोनों आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां टर्मिनल-3 पर मौजूद सीआइएसएफ अधिकारियों को उन्होंने पूरी बात बताई।

उन्होंने बताया कि उनके बेटे को आइजोल जाना था। इसके बाद एयरपोर्ट पर आइजोल जाने वाले विमान के बोर्डिंग गेट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज खंगालने के क्रम में पाया गया कि युवक वहीं टर्मिनल में बोर्डिंग गेट के पास ही मौजूद है। इसके बाद युवक को माता-पिता के हवाले किया गया। युवक भूलने की बिमारी के चलते वह भूल गया था कि उसे कहां जाना है।

सुकेश ने फिर कहा-आप नेताओं को दिए 60 करोड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

200 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपित ने कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि उसे मंडोली जेल में किया जा रहा परेशान

नई दिल्ली-पटियाला कोर्ट में पेशी के बाद बाहर आते सुकेश चंद्रशेखर। जागरण

200 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर कहा कि उसने आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को 60 करोड़ रुपये दिए थे। इस पर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आप से जवाब मांगा है।

सुकेश से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के कोर्ट में पेशी के वक्त सुकेश और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज आमने-सामने हुए। दोनों एक-दूसरे से नजरें चुराते दिखे। उसने कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि उसे मंडोली जेल में परेशान किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। उसकी शिकायतें कोर्ट तक आने नहीं दी जा रहीं। पेशी के बाद बाहर निकलने पर सुकेश ने कहा कि आप के नेताओं को 60 करोड़ रुपये दिए थे। आप को लेकर लिखी गई चिट्ठियों के चलते उस पर जेल में दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी, 2023 को होगी। सुकेश के वकील अनंत मलिक ने कहा कि उपराज्यपाल की ओर से गठित समिति के समक्ष भी यह आरोप दोहराया था।

ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने आरोप-पत्र के अंश पढ़ते हुए कहा कि सुकेश इस मामले का मास्टरमाइंड है। जेल में उसके पास से कई मोबाइल भी मिले थे। पीड़िता अदिति सिंह से ठगी के लिए सुकेश ने पहला फोन लैंडलाइन से किया था। अदिति से रकम ठगने की बात सुकेश ने स्वीकार की है, जोकि करीब 57 करोड़ रुपये है। जेल अधिकारियों को दिए उपहारों के बारे में भी जानकारी कोर्ट को दी गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह आरोपों पर शर्ट नोट बनाकर दाखिल करें। साथ ही सुकेश की पत्नी लीना मारिया की अटैच की गई 26 करोड़ रुपये की संपति को कब्जे में लेने का आदेश ईडी को दिया।

जैकलिन ने बहरीन जाने की अनुमति मांगी : अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज ने परिवार के पास बहरीन जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। वह 23 दिसंबर से पांच जनवरी, 2023 तक वहां रहना चाहती हैं। अर्जी पर सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

सुकेश के आरोप पर जवाब दे आप : भाजपा : दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने सुकेश चंद्रशेखर के उन आरोपों पर आप से जवाब मांगा है, जिसमें आप नेताओं को 60 करोड़ रुपये देने की बात कही है। खुराना ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार-बार यह कह कर सुकेश के आरोपों पर जवाब देना टालते रहे की एमसीडी चुनाव की वजह से भाजपा यह सब करा रही है। अब तो कोई चुनाव नहीं है और सुकेश ने मीडिया से कहा कि है कि उसने 60 करोड़ रुपये दिए हैं।

पुलिस हुई सुस्त तो इंसाफ के लिए बेटी ने कसी कमर

अरविंद कुमार द्विवेदी, नई दिल्ली

हिट एंड रन

- कार से आटो में टक्कर मारी, सड़क पर गिरे आटो चालक को कुचलते हुए कार चालक भागे
- लाजपत नगर का मामला, आरोपितों ने पीड़ित को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया
- सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ हादसा, अभी आरोपितों तक नहीं पहुंची पुलिस

सुकन्या नागपाल। स्वयं

लाजपत नगर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक आटो में टक्कर मारी गई। फिर सड़क पर गिरे आटो चालक को कुचलते हुए कार चालक भाग गया। फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपितों का पता नहीं लगा सकी है। हालांकि पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मृतक की बेटी एडवोकेट सुकन्या ने कमर कस ली है। सुकन्या का कहना है कि आरोपितों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए वह घटनास्थल के आसपास की खाक छान रही हैं। उन्हें पुलिस जांच की सुस्त रफ्तार से काफी निराशा हुई है। सुकन्या ने कहा कि पुलिस ठीक से जांच करे, वह कोर्ट में भी पुलिस को सहयोग करेंगी।

जानकारी के अनुसार, मधु विहार निवासी अशोक नागपाल (60) आटो चलाते थे। 15 दिसंबर की रात करीब डेढ़ बजे वह लाजपत नगर में बीर सावरकर मार्ग पर एक सवारी छोड़ने जा रहे थे। तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वह आटो से छिटककर सड़क पर जा गिरे। टक्कर मारने वाली कार भी फुटपाथ से टकराकर रुक गई। इसके बाद कार चालक ने अशोक पर गाड़ी चढ़ाते हुए कार बैक की और भाग गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पंबुलेंस को काल कर जानकारी दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। अस्पताल ले जाने पर अशोक को मृत घोषित कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के बाद तीन लोग गाड़ी से उतरे थे। इस दौरान कार चला रही लड़की पीछे बैठ गई और उनमें से एक युवक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फुटेज में भी कुछ लोग गाड़ी से उतरते और फिर बैठते हुए नजर आ रहे हैं।

पुलिस सूत्र ने बताया कि मौके पर मिली कार की टूटी हेडलाइट फोक्सवैगन पोलो कार की लग रही है। हालांकि कंपनी में ले जाने पर बताया गया कि यह कंपनी की ओरिजनल हेडलाइट नहीं है। मोडिफाइड लोकल लाइट है। अभी पूरी तरह से कार की पहचान नहीं हो सकी है। कुछ अच्छी क्वालिटी की फुटेज की तलाश की जा रही है जिससे गाड़ी का नंबर व अन्य जानकारी मिल सके।

बेटी ने लगाया लापरवाही का आरोप : अशोक नागपाल की बेटी एडवोकेट सुकन्या का कहना है कि घटनास्थल के आसपास बहुत से सीसीटीवी कैमरे हैं जिनसे पुलिस को गाड़ी का नंबर से लेकर आरोपितों की तस्वीरें मिल सकती हैं। सुकन्या ने खुद भी कुछ सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ, वहां पर खंभे पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन अब वहां कैमरा नहीं है। इससे भी संदेह उत्पन्न हो रहा है।

बाजार के दुकानदारों की मदद ले रही बेटी : पुलिस जांच की सुस्त चाल के कारण हादसे के करीब एक सप्ताह बाद भी आरोपितों का सुराग नहीं लग सका है। सुकन्या पूरी मार्केट के दुकानदारों से संपर्क कर फुटेज जुटा रही हैं। सुकन्या ने बताया कि पुलिस को फुटेज आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं लेकिन उन्हें इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।

मिशन एडमिशन

डीयू के 30 कालेजों में अभी भी 11 हजार से ज्यादा सीटें खाली

उत्तरी और दक्षिणी परिसर के बाहर के हैं ये सभी कालेज, विशेष स्पाट राउंड के लिए आवेदन का समय खत्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

91 कालेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय कुल

13 कालेज उत्तरी परिसर और 19 कालेज दक्षिणी परिसर में हैं

59 कालेज डीयू के कैंपस के अंतर्गत आते हैं

16 सीटें खाली हैं बीकाम व बीकाम (आनर्स) में डा. भीमराव अंबेडकर कालेज में

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा स्नातक की बची हुई खाली सीटों के लिए आयोजित किए जा रहे विशेष स्पाट राउंड के लिए 30 कालेजों में 11 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। ये कालेज उत्तरी व दक्षिणी परिसर के बाहर के कालेज हैं। डीयू के कुल 91 कालेज हैं। इनमें उत्तरी परिसर में 13 व दक्षिणी परिसर में 19 कालेज स्थित हैं।

छात्र हमेशा डीयू के इन दोनों परिसरों के अंतर्गत आने वाले कालेजों को दाखिले के लिए वरीयता देते हैं या कालेजों की रैंकिंग को। इसलिए हर साल परिसर के अंतर्गत आने वाले कालेजों में अन्य कालेजों की तुलना में सबसे पहले सीटें फुल होती हैं। फोरम आफ एकेडेमिक्स फार सोशल जस्टिस के चेयरमैन डा. हंसराज सुमन ने जारी खाली सीटों की गणना करते हुए बताया कि डीयू द्वारा जारी 30 कालेजों के अलग-अलग कोर्सेज में कुल 11152 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर दाखिले के लिए विशेष स्पाट राउंड में आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रात 11.59 बजे तक थी। अब 22 दिसंबर की सुबह 10 बजे डीयू द्वारा सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी। 23 दिसंबर शाम 4.59 बजे तक छात्र सीट लाक करके दाखिला ले सकेंगे। अगर कालेजवार खाली सीटों की बात करें, तो अदिति महाविद्यालय में 25 से अधिक कोर्सेज जैसे बीए (आनर्स) भूगोल, सामाजिक कार्य, हिंदी पत्रकारिता, बीकाम (आनर्स) और बीकाम में सीटें खाली हैं। देशबंधु कालेज में बीए (प्रोग्राम) और बीएससी (प्रोग्राम) में सीटें खाली हैं। इसी तरह डा. भीम राव अंबेडकर कालेज में अन्य कोर्सेज के अलावा बीकाम व बीकाम (आनर्स) में 16-16 सीटें खाली हैं। राजधानी कालेज में गणित में 11 सीटें खाली हैं।

श्रेणीवार खाली सीटों की सूची

श्रेणी	सीट
सामान्य	2638
ओबीसी	2149
एससी	1342
एसटी	1994
पीडब्ल्यूडी	1662
ईडब्ल्यूएस	1367

उत्तरी और दक्षिण परिसर के प्रमुख कालेज : भिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस, किरोड़ी मल, हंसराज, दौलतराम, हिंदू, रामजस, श्री राम कालेज आफ कामर्स, आइपी महिला कालेज, लेडी इरविन कालेज, देशबंधु, आचार्य नरेंद्र देव, रामानुज, दयाल सिंह, अरबिंदो, लेडी श्रीराम महिला कालेज, जीसस एंड मेरी कालेज, श्री वेंकटेश्वरा कालेज।

यूजी-पीजी में 31 दिसंबर से दाखिले बंद : डीयू प्रशासन ने स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिले के लिए 31 दिसंबर को अंतिम तिथि घोषित कर दी है। इसके बाद इन कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। पीजी की दौथी स्पाट राउंड सूची डीयू 21 दिसंबर को वेबसाइट पर जारी करेगा। 22 दिसंबर सुबह 10 से 23 दिसंबर रात 11.59 बजे तक छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। 24 दिसंबर शाम पांच बजे तक कालेज आवेदन व प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। 25 दिसंबर रात 11.59 बजे तक फीस जमा कर सकेंगे।

****

12000 पदों के लिये जारी किए गए हैं विज्ञापन केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण, गैर-शिक्षण श्रेणी के लिए। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देशभर में 14 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें सबसे अधिक 1277 रिक्तियां मप्र में हैं। 1220 पद तमिलनाडु में खाली हैं।

घुसपैठ के लिए चीन के राजदूत को तलब क्यों नहीं किया : रमेश

पलटवार ▸ चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की

कांग्रेस ने कहा, घुसपैठ को धारणा का अंतर बताना बंद करे मोदी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के क्रम में मंगलवार को कांग्रेस ने विदेशमंत्री एस.जयशंकर पर पलटवार करते हुए राजग सरकार की चीन नीति पर सवालों के तीर दागे। चीन से रिश्ते सामान्य नहीं होने के विदेशमंत्री के बयान पर पार्टी ने कहा कि ऐसा है तो पाकिस्तान की तरह चीनी राजदूत को अब तक क्यों नहीं तलब किया गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा, चीनी घुसपैठ को 'धारणा का अंतर' बताकर उसे वैध ठहराए जाने के बजाय सरकार को इसके खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए और विदेशमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 की यथास्थिति कब तक बहाल होगी।

विदेशमंत्री ने जवानों के बारे में राहुल गांधी के बयान पर सोमवार को एतराज जताया था। कांग्रेस के संचार महासचिव

जयराम रमेश। फाइल फोटो

जयराम रमेश ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसका जवाब देते हुए कहा कि विदेश मंत्री का कहना है कि हम चीन पर दबाव बना रहे हैं फिर हमारा दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक क्यों हैं? एलएसी पर 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली सुनिश्चित किए बिना हम कैलाश पर्वत श्रेणी में अपनी सामरिक रूप से लाभप्रद स्थिति से पीछे क्यों हट गए? हम अधिक आक्रामक क्यों नहीं हुए और चीनियों को पीछे हटने को मजबूर करने के लिए जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की जैसा 1986 और 2013 में किया गया था? जयराम ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि हम अपना दावा पुरजोर ढंग से पेश करने की बजाए चीनी घुसपैठ को 'धारणा का अंतर' बताकर उसे वैध ठहराना कब बंद करेंगे? कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम विदेश मंत्री के इस कथन से सहमत हैं कि हमारे जवानों का 'सम्मान, सराहना और सत्कार' किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ डटकर खड़े हैं, लेकिन गलवन की घटना जिसमें हमारे 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान किया उसके बाद 19 जून, 2020 के पीएम मोदी के बयान 'न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है और न ही कोई घुसा हुआ है' में क्या यह भावना और सम्मान था? चीन के साथ 2021-22 में 95 बिलियन डालर के आयात और 74 बिलियन डालर के व्यापार घाटे के साथ चीन पर हमारी व्यापार निर्भरता रिकार्ड उच्च स्तर पर क्यों पहुंच गई है? इस स्थिति में सितंबर 2022 में रूस के वोस्तोक-22 अभ्यास में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास क्यों किया? जयराम ने कहा, विदेशमंत्री ने एलएसी में एकतरफा बदलाव नहीं करने देने की बात कही है लेकिन क्या चीनी सैनिकों ने दो सालों से डेपसांग में 18 किमी अंदर आकर यथास्थिति नहीं बदली?

शराब पीकर पंजाब को चला रहे भगवंत मान : हरसिमरत कौर

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा सदस्यों ने मांग की कि मादक पदार्थों के लती लोगों को जेल भेजने के बजाय सरकार को उनके लिए और पुनर्वास केंद्र बनाने चाहिए।

हरमीत कौर। फाइल

इस दौरान शिअद बादल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर राज्य को शराब पीकर चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ऐसे हैं तो राज्य की स्थिति का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है।

हरसिमरत कौर ने कहा, 'मादक पदार्थ स्कूलों में भी प्रवेश कर गए हैं। कोई भी यहां सुरक्षित महसूस नहीं करता। कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला ने मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए कानून के सख्ती से अनुपालन की मांग की प्रमुक के वीरासवामी कलानिधि ने सरकार से अनुरोध किया कि हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक पुनर्वास केंद्र होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस सरकार को हर हाल में ड्रग्स की समस्या पर रोक लगानी होगी। वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिथुन रेड्डी और राकोपा की सुप्रिया सुले ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।

सुरजेवाला ने किया पार्टी अध्यक्ष खरगे का बचाव

प्रथम पृष्ठ से आगे

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बचाव करते हुए कहा, 'खरगे जी ने बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है। सुरजेवाला ने कहा, जब भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में है, जब वर्तमान शासक चीन की दुस्साहसपूर्ण घुसपैठ पर खामोश है तो यह हर देशभक्त की जिम्मेदारी है कि वह सरकार में बैठे लोगों की चुप्पी और ढोंग पर सवाल उठाए।' ध्यान रहे कांग्रेस के कई नेता पूर्व में भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार तवांग के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और देश को सही जानकारी नहीं दे रही है। वह इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।

चीन पर चर्चा का नोटिस फिर खारिज : कांग्रेस सदस्य सैयद नसीर हुसैन समेत संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों की ओर से चीन मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर नोटिस दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस सहित विपक्षी दल ही चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में अवरोध पैदा कर रहे हैं।

रणदीप सुरजेवाला। फाइल फोटो

नेहरू सरकार को कमजोर इच्छाशक्ति का कहने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति : शून्यकाल के दौरान लोकसभा में भाजपा सदस्य प्रतापराव चिखालिकर ने कहा कि नवंबर, 1962 में संसद में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र को चीन से वापस लेने का प्रस्ताव पारित करने के बावजूद नेहरू सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस पर कांति चिटंबरम समेत कई कांग्रेस सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की। इस दौरान प्रतापराव ने यह भी कहा कि भारत के लोगों को अब विश्वास है कि 1962 के युद्ध में चीन के कब्जे में गए भूभाग को मोदी सरकार ही वापस लाए।

तीन यूट्यूब चैनल फर्जी खबरें फैला रहे हैं: सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं को लेकर झूठे और सनसनीखेज दावे करने और फर्जी खबरें फैलाने वाले तीन यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि न्यूज हेडलाईंस, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव नाम के यूट्यूब चैनल टीवी समाचार चैनलों और उनके समाचार प्रस्तोता के थंबनेल और छवियों का उपयोग दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कर रहे थे कि उनके द्वारा साझा की गई खबर प्रामाणिक है। ये यूट्यूब चैनल अपने वीडियो पर विज्ञापन दिखा रहे थे और गलत सूचनाओं के माध्यम से कमाई भी कर रहे थे।

चालीस से अधिक फैक्ट-चेक श्रृंखला के क्रम में पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट-चेक इकाई (एफसीयू) ने यूट्यूब के इस तरह के तीन चैनलों का पर्दाफाश किया है। इन यूट्यूब चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर थे। इनके लगभग सभी वीडियो फर्जी निकले और इनके वीडियो को 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया है। ये तीनों यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट, प्रधान न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, कृषि ऋणों को माफ करने आदि के बारे में झूठी और सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं। इनमें फर्जी खबरें भी शामिल रहती हैं।

नोटबंदी पर संविधान पीठ चार जनवरी तक सुना सकती है फैसला

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : छह साल पहले 2016 को हुई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ चार जनवरी तक फैसला दे सकती है। चार जनवरी तक फैसला आने की संभावना इसलिए है क्योंकि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष जस्टिस एस.अब्दुल नजीर चार जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल शीतकालीन अवकाश चल रहा है। कोर्ट दो जनवरी को खुलेगा। ऐसे में दो जनवरी से चार जनवरी के बीच नोटबंदी पर फैसला आने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने आठ नवंबर, 2016 को 500 और 1000 के नोटों की बंदी की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में कुल 58 याचिकाएं लंबित हैं जिनमें केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी.रामासुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई कर सात दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब चार जनवरी को फैसला आने की उम्मीद है।

कोरोना से चिंतित केंद्र ने राज्यों से की अपील पाजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गाइडलाइन अनुपालन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी
- कई देशों में संक्रमण बढ़ा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे समीक्षा बैठक

कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने देश में इसकी रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे सभी पाजिटिव सैंपल की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग में जुट जाएं ताकि इसका पता चले कि कोविड का कोई नया वैरिएंट तो नहीं पनप रहा है। गौरतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द चीन की बड़ी आबादी फिर से चपेट में होगी।

जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन तथा अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया बुधवार को एक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में दुनियाभर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य, आयुष, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी

राजेश भूषण। फाइल फोटो

विभाग के सचिव, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पाल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष एनएल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि उभर रहे वैरिएंट पर निगरानी रखने के लिए पाजिटिव सैंपल की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग पर पूरा ध्यान दिया जाए। टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोविड से मुकाबले के लिए उपयुक्त व्यवहार की पांच स्तरीय रणनीति से इस महामारी पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। इसका नतीजा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को साप्ताहिक आधार पर 12 हजार मामलों तक सीमित किया जा सका है, लेकिन दुनिया में इसका खतरा पूरी तरह टला नहीं है। वर्तमान में विश्व में एक सप्ताह में 35 लाख मामले सामने आए हैं। पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने मंत्रालय की ओर से जून में जारी की गई निगरानी की संशोधित प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया है और इसके अमल पर जोर दिया है। इसके मुताबिक नए वैरिएंट की चुनौती को लेकर जल्दी जांच, आइसोलेशन, टेस्टिंग और संदिग्ध तथा पाजिटिव मामलों के सही प्रबंधन पर जोर दिया गया है। राजेश भूषण के मुताबिक मौजूदा वैरिएंट के रुझानों की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है।

संसद प्रश्नोत्तर

नक्सली हिंसा की घटनाओं में 11 साल में 77% की कमी : नित्यानंद राय

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 2010 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2010 में नक्सली हिंसा की 2,213 घटनाएं हुई थीं जो 2021 में घटकर 509 हो गईं। इस तरह की घटनाओं में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत के मामलों में भी 85 प्रतिशत की कमी आई है। 2010 में 1,005 लोगों की मौत हुई थी जो 2021 में घटकर 147 रह गई। राय ने कहा कि राष्ट्रीय नीति के सख्ती से क्रियान्वयन से वाम चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में लगातार कमी आई है।

2019 से अब तक साइबर अपराध की छह लाख शिकायतें दर्ज की गईं : वर्ष 2019 में सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू होने के बाद से अब तक साइबर अपराध की छह लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि देश में सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम अमल में आने के बाद से 12 दिसंबर, 2022 तक साइबर अपराध की छह लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। जबकि 1.11 लाख से ज्यादा शिकायतों से जुड़े मामलों में 188 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई। कहा कि सभी तरह के साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है।

राज्यों को एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति : केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की अनुमति दी है। कोरोना के शिकार लोगों के स्वजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रविधान है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत सहायता के वितरण सहित आपद प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार एसडीआरएफ की मदद से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत प्रदान करने का कार्य करती हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए राज्यों को एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति दी है।

साकार हो रहा मोदी का 'न्यू इंडिया' व 'युवा भारत' का सपना : स्मृति इरानी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्रीय मंत्री ने गिनाई मोदी सरकार की आठ वर्ष की उपलब्धियां

मोदी सरकार की आठ वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवावस्था में अपनी डायरी के पन्नों पर ''न्यू इंडिया'' और ''युवा भारत'' का जो सपना शब्दों में पिरोया था, वह आज साकार होता नजर आ रहा है। भारत मजबूती से लगातार नई पहल के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनौतियों का सामना किया है, वह अपने आप में काबिलेतारीफ है।

केंद्रीय मंत्री इरानी ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आठ वर्ष में ही भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। देश की आर्थिक प्रगति में युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप

स्मृति इरानी। फाइल फोटो

इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना जैसी कई योजनाओं को धरातल पर उतारकर प्रधानमंत्री ने युवाओं को सशक्त बनाया है। मेक इन इंडिया ने भारत को नया रूप दिया है। फिट इंडिया मूवमेंट ने भारत की तस्वीर बदली और डिजिटल इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए स्मृति इरानी ने कहा कि 656 जिलों में 84,400 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ भारत विश्वस्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। भारतीय यूनिकार्न का कुल मूल्यांकन 332.7 अरब डालर पर पहुंच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, प्रोडक्ट लिंक इन्सेंटिव योजना, गरीब कल्याण अन्य योजना आदि की उपलब्धियों के आंकड़े भी साझा किए।

नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह युवाओं को विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके हौसलों के साथ है। इसी तरह खेल की दिशा में भी मोदी सरकार ने काफी काम किया है। इसी प्रोत्साहन का परिणाम है कि भारत ने ओलंपिक, पैरालंपिक और कामनवेल्थ खेलों में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया।

कैग ने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के कदमों में देरी पर जताई चिंता

नई दिल्ली, प्रेट्र: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने तटीय क्षेत्रों एवं नौसैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा मजबूत करने के कदमों में देरी पर चिंता जताई है। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का निर्णय लिया गया था। फरवरी, 2009 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने तीन साल के भीतर सुरक्षा मजबूत करने की बात कही थी। मुंबई हमले के आतंकियों ने समुद्री रास्ते से ही घुसपैठ की थी।

संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि सागर प्रहरी बल में फास्ट इंटरसेप्शन क्राफ्ट (एफआइसी) की तैनाती में 13 से 61 महीने तक की देरी हुई। कुछ नौसैन्य बंदरगाहों पर जून, 2022 तक भी उस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया था, जैसा सीसीएस ने कहा था। कैग ने एफआइसी की उपलब्धता एवं उनके प्रयोग को भी निम्नस्तरीय पाया है। एक अन्य विश्लेषण में कैग ने कहा कि बीजीटी की संख्या आवश्यकता से अधिक पाई गई।

यूनियन कार्बाइड स्थल के मामले को पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया

नई दिल्ली, प्रेट्र : रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल के यूनियन कार्बाइड साइट पर पड़े रासायनिक कचरे के निपटान के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बगवत खुबा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, भोपाल में यूनियन कार्बाइड साइट से रासायनिक कचरे के निपटान के लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, व्यय विभाग से धनराशि जारी करने का अनुरोध करने से पहले जहरीले कचरे के निपटान के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लगातार स्थिति की समीक्षा की है और मध्य प्रदेश सरकार को यूनियन कार्बाइड संयंत्र कचरे के निस्तरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं।

आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया 4.21 करोड़ मरीजों का इलाज

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 4.21 करोड़ मरीजों का इलाज किया गया है। इस पर लगभग 49,468 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी जो सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत लोगों को सुलभ और किफायती इलाज प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

हवाला लेनदेन में आनलाइन गेमिंग का प्रयोग ईडी ने जब्त किए 213 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने उन मामलों में अपराध की 212.91 करोड़ रुपये की आय कुर्क की है, जहां आनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग साइट स/ऐप का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग और हवाला लेनदेन के लिए किया गया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि ईडी, साइबर अपराधों और क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े कई मामलों की जांच कर रहा है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि मनी लांड्रिंग और हवाला लेनदेन के लिए आनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग साइटों का उपयोग किया गया था। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, 'इन मामलों में 16 दिसंबर, 2022 तक, 212.91 करोड़ रुपये की पीओसी की पहचान की गई है, जो पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्क/ फ्रीज/जब्त की गई है। साथ ही, इन मामलों में 03 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।' पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आनलाइन गेमिंग विनियमन के सभी पहलुओं को देखने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल का गठन किया है। पंकज ने पिछले दिनों लोकसभा में बताया था कि अप्रैल 2019 से लेकर नवंबर 2022 के गेमिंग कंपनियों ने 23000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की है।

संसद में व्यंजन तैयार करने कर्नाटक और राजस्थान से आए थे रसोइए

प्रथम पृष्ठ से आगे

भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। मोटे अनाज से तैयार व्यंजनों का उत्सव मनाया जाएगा। इसी क्रम में आगामी वर्ष के स्वागत के लिए संसद में आयोजित कृषि मंत्रालय के इस भोज में मंत्रियों और पक्ष-विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पौषक मोटे अनाज से बने कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए। व्यंजन तैयार करने वाले ज्यादातर रसोइए कर्नाटक और राजस्थान से आए थे। संसद परिसर में मिलेट्स आधारित रंगोली को भी खूबसूरत ढंग से सजाया गया था, जिसमें देशभर की प्राथमिक पोषक अनाज वाली फसलों को प्रदर्शित किया गया। अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के लिए विभिन्न प्रचार सामग्री के साथ एक कोलाज भी प्रदर्शित किया गया। अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का औपचारिक शुभारंभ समारोह इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने किया था, जिसमें भारतीय दल ने पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लिया था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत में बताया कि मोटे अनाज वाली फसलों की खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों के साथ कम उपजाऊ जमीन में भी होती है, जिसमें कीटनाशकों के प्रयोग की बहुत कम जरूरत होती है। मोटे अनाजों की खेती मूलतः एशिया और अफ्रीका में शुरू हुई थी, जो पूरी दुनिया में होने लगी।

एक मेज पर दिखे मोदी और खरगे : लंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एक मेज पर नजर आए। उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला भी बैठे थे। मोदी और खरगे का साथ में लंच करना इसलिए चर्चा में रहा, क्योंकि खरगे के बयान के कारण दिनभर भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग चलती रही थी।

भारतीय समाज समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं: सुशील मोदी

नई दिल्ली, एएनआइ : समलैंगिक विवाह पर अपना रुख दोहराते हुए भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय समाज समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और यह भारतीय संस्कृति व परंपरा के लिए भी अनुचित है। संसद के बाहर सुशील मोदी ने कहा कि कुछ बामपंथी और उदार कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए और समलैंगिक विवाह को कानून सम्मत बनाने की मांग की। यह उचित नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठकर दो जज इस पर फैसला करें। अदालत जाने से पहले इस मुद्दे पर संसद में सदस्यों के बीच चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले सुशील मोदी ने सेमवार को राज्यसभा में भी कहा था, 'भारत में समलैंगिक विवाह मुस्लिम पर्सनल ला जैसे किसी भी पर्सनल ला या किसी भी संहिताबद्ध कानूनों में स्वीकार्य या मान्यता प्राप्त नहीं है। समलैंगिक विवाह पर्सनल ला के संतुलन में तबाही मचा देगा।'

ईडी ने सांसदों, विधायकों के खिलाफ 87 मनी लांड्रिंग मामलों में की जांच

- धन शोधन निवारण अधिनियम एक जुलाई 2005 से प्रभाव में आया
- फं 36 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 1,082 केसों में विभिन्न स्तर पर ट्रायल चल रहा

नई दिल्ली, आइएएनएस: प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बीते पांच वर्षों में धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) 2002, के प्राविधानों के तहत लगभग 87 मामलों में सांसदों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ जांच की है। इसमें मौजूदा और पूर्व दोनों माननीय शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि पिछले पांच सालों में 59 अभियोजन शिकायतें विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई हैं, जो ट्रायल के अलग-अलग चरणों में हैं। पंकज चौधरी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम एक जुलाई 2005 से प्रभाव में आया था। तब से आज की तारीख तक सिर्फ 36 मामलों में सुनवाई पूरी हो पाई है और शेष 1,082 केसों में विभिन्न स्तर पर ट्रायल चल रहा है। जबाब में आगे कहा गया कि मनी लांड्रिंग के अपराध का ट्रायल 36 निर्णीत मामलों में से केवल 21 मामलों में योग्यता के आधार पर पूरा किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 20 मामलों में 31 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। शेष 15 मामलों में, मनी लांड्रिंग के अपराध का मुकदमा विधेय एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर विधेय अपराध को रद करने के कारण गुण-दोष के आधार पर आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि, इन मामलों में उच्च न्यायालयों के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी गई है। राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा नया नहीं है। कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं के खिलाफ भी मनी लांड्रिंग के मामले दर्ज हैं।

****

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

144 से बढ़ाकर 160 किया है भाजपा ने कंटिन सीटों पर जीतने का लक्ष्य मिशन- 2024 के तहत। इसके लिए 21 और 22 दिसंबर को दो-दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 21 दिसंबर, 2022

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को मिल सकता है विस्तार

▶ अगले महीने राजधानी दिल्ली में होगी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

▶ आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा और संगठनात्मक गतिविधियों की होगी समीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है। अगले महीने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इस संबंध में फैसला हो सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी होगी।

आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक चुनावों को स्थगित करना इस बैठक का अहम मसला रहने का अनुमान है। संगठन के चुनाव स्थगित होंगे तो नड्डा को स्वतः ही सेवा विस्तार मिल जाएगा। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनका तीन साल का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि अप्रैल-मई, 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के आंतरिक चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पूर्व पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भी 2019 में विस्तार मिला था। चुनाव परिणाम के बाद सांगठनिक चुनाव हुए और नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया। नड्डा संगठन का पुराना चेहरा हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व से उनके अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी उन पर भरोसा है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल कर्नाटक, तेलंगाना, मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव होने हैं।

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

बंगाल के भाजपा नेताओं को गुटबाजी छोड़ एकजुट होने की दी सलाह

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंचायत चुनाव एवं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में पार्टी के सांसदों व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सोमवार रात दिल्ली में हुई बैठक कर एकजुटता का संदेश दिया है।

नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। प्रदेश नेतृत्व को ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन करने को भी कहा। बैठक में सुवेंदु ने नड्डा को बताया कि बंगाल में भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व इनसे निपटने में सहयोग करे। इस पर नड्डा ने सुवेंदु को बताया कि केंद्रीय नेतृत्व इससे अवगत है और इसपर विचार कर रहा है। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री व बनगांव से सांसद शांतनु ठाकुर ने सीएए का मुद्दा उठाया। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सीएए देश का कानून है। यह लागू होगा। समय का इंतजार है।

पीएम मोदी व शाह से मिले सुवेंदु, टीएमसी को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी : बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुवेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए टीएमसी को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया। सुवेंदु ने बताया कि उन्होंने राज्य में केंद्र की व्यापक भ्रष्टाचार से भी गृह मंत्री को अवगत कराया है।

महाराष्ट्र के पंचायत चुनावों में भाजपा का बड़ी सफलता का दावा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में छह माह पहले हुई उथल-पुथल के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा को अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जबकि, शिवसेना का उद्धव गुट चौथे नंबर पर खिसकता नजर आ रहा है। राज्य में 18 दिसंबर को हुए ग्राम पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। राज्य के 34 जिलों में 7,135 ग्राम पंचायतों में सीधे सरपंच एवं पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे। जिसकी गिनती मंगलवार सुबह शुरू हुई। वोटों की गिनती में ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा बड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि अब तक राज्य की 2,482 ग्राम पंचायतें जीतकर भाजपा अन्य दलों की तुलना में सबसे आगे चल रही है।

बावनकुले के अनुसार, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बालासाहब की शिवसेना को भी 842 ग्राम पंचायतों में सफलता मिली है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस जीत का श्रेय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देते हुए कहा है कि राज्य की जनता इसी प्रकार शहरी निकाय चुनावों में भी भाजपा एवं एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी सफलता देगी। अब तक आए चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारे गठबंधन को शानदार जीत मिली है। अब हम पूरे कोकण और विदर्भ में फैल गए हैं।

▶ चौथे नंबर पर खिसकता नजर आ रहा शिवसेना का उद्धव गुट

देवेंद्र फडणवीस। फाइल

न्यूज गैलरी

गुजरात में आप नेता ईटालिया के विरुद्ध हुई कार्रवाई

अहमदाबाद : भावनगर में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल ईटालिया की पुलिस ने एक पुराने मामले में धरपकड़ की। आप नेता पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया तथा बाद में निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ दिया। धार्मिक परंपरा और रामकथा वाचकों पर टिप्पणी कर कई बार ईटालिया विवाद पैदा कर चुके हैं। (राब्यू)

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा- कांग्रेस आतंकियों की पार्टी

उत्तर कन्नड, (कर्नाटक) : कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे आतंकियों की पार्टी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार आतंकवादियों का समर्थन कर कांग्रेस 'आतंकवादियों' की पार्टी बन गई है। मंगलवार को यहां पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कटील ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस आतंकवादियों का बचाव कर रही है। सिद्दरमैया के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार ने आतंकवाद, नशाखोरी तथा रेत माफिया का समर्थन किया था। येदियुरप्पा और बोम्मई के नेतृत्ववाली भाजपा सरकार ने इन माफिया पर अंकुश लगाया। आजादी के पहले वाली कांग्रेस अब नहीं रही, बदल गई है। (आइएएनएस)

सुक्खू सरकार ने पलटे जयराम के निर्णय, कई कार्यालय बंद, कुछ का दर्जा घटाया

फैसला ▶ प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय किए बंद

60 पशु औषधालय- डिस्पेंसरी का दर्जा घटाया बंद किए, 12 सब्जी मंडियां खोलने का निर्णय पलटा

जागरण टीम, शिमला

प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को पूर्व भाजपा सरकार के कई निर्णयों को पलट दिया। भाजपा शासन में खोले गए 100 से अधिक कार्यालयों व संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी हुआ तो स्तरोन्नत का दर्जा घटा दिया गया। राज्य बिजली बोर्ड ने 32 कार्यालय बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में 12 सब्जी मंडियां खोलने का निर्णय भी पलट दिया गया। पशुपालन विभाग में स्तरोन्नत हुए या खोले गए 60 पशु औषधालयों व डिस्पेंसरियों का बंद किया गया है या दर्जा घटाया गया है।

प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर 32 कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। जिन कार्यालयों को बंद किया गया है उनमें तीन परिचालन वृत, 12 विद्युत मंडल, 17 विद्युत उपमंडल शामिल हैं। 12 दिसंबर को नई सरकार ने नए खोले कार्यालयों को बंद करने के आदेश दिए थे। नए डिवीजन और परिचालन वृत बंद होने के बाद इनका नियंत्रण पुरानी व्यवस्था में बदल जाएगा। ये कार्यालय अप्रैल में खोले गए थे। उधर, पूर्व सरकार के समय बजट प्रविधान के बिना खोले गए या स्तरोन्नत किए 60 पशु औषधालय और पशु डिस्पेंसरी का बंद किया गया है या दर्जा घटा दिया गया है। सुक्खू सरकार ने कृषि विभाग के तहत राज्य के विभिन्न भागों में मार्केट बोर्ड के माध्यम से 12 मंडियां खोलने का निर्णय भी पलट दिया है। इनमें कई ऐसे हैं, जिन्हें वित्त विभाग की मंजूरी के बिना खोला गया है। बागवानी विभाग ने अधिकारियों को वीरवार तक ऐसे कार्यालयों की जानकारी भेजने के लिए कहा है, जो बिना बजट और आवश्यकता को दरकिनार रखकर खोले गए या स्तरोन्नत किए गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद इस वर्ष अप्रैल के बाद खोले गए सरकारी कार्यालयों की जांच करने को कहा गया है। सरकार ने विधानसभा चुनाव से दो माह पहले के दौरान स्तरोन्नत किए शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों सहित सभी विभागों में बिना बजट घोषणाओं के तुरंत निरस्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के एथलेटिक्स कोच गोपाल ठाकुर का सेवाविस्तार सरकार ने रद कर दिया है। इससे खेल स्टेडियम में सेना व राष्ट्रीय खेलों का प्रशिक्षण ले रहे करीब 400 खिलाड़ियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू। फाइल

कार्यालय बंद करने पर जाएंगे कोर्ट : जयराम

जागरण संवाददाता, शिमला : पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के बिजली कार्यालयों को बंद करने के निर्णय का भाजपा विरोध करेगी। हे। इन कार्यालयों के खोलने का निर्णय सही था, जिसमे बोर्ड की स्वीकृति ली गई थी। सरकार के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय जाएंगे। जारी प्रेस बयान में कहा कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जनहित के निर्णयों पर राजनीति कर रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री बदला-बदली की भावना से राजनीति कर रहे हैं। यह सरकार केवल निर्णय पलटने आई है।

हिमाचल में पूरा नहीं हो सका 10 दिन में वादे पूरा करने का दावा

राज्य ब्यूरो, शिमला

प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार को सत्ता में आए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर 1.71 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) देने का पहला वादा पूरा नहीं हो सका है। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में एक लाख नौकरियां देने का कांग्रेस का दूसरा वादा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। उस समय सुक्खू ने दस दिन के भीतर कांग्रेस की दस गारंटियों में से दो को पहली मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लाने की घोषणा की थी। मौजूदा स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू कोरोना संक्रमित होकर दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में आइसोलेट हैं। दिसंबर की 20 तारीख भी बीत गई है, लेकिन अभी तक सरकार मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। अब स्थिति ऐसी बन रही है कि शायद मंत्रिमंडल नए साल में ही गठित हो।

ओपीएस लागू नहीं के इंतजार में कर्मचारी : विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में सेवारत पुरानी पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत एक लाख 71 हजार कर्मचारियों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही कांग्रेस पहला कार्य ओपीएस लागू करने का करेगी। एनपीएस के तहत 2003 के बाद सरकारी नौकरी करते हुए 20 हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा या नहीं, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है, जिन्होंने दस साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया।

सुक्खू ने दिल्ली से दिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग के अधिकारियों को ओपीएस लागू करने का प्रस्ताव तैयार रखने के लिए कहा है। उनके शिमला लौटने से पहले वित्त विभाग ओपीएस लागू करने का प्रस्ताव तैयार रखें। कांग्रेस सरकार 10 गारंटियों को पूरा करेगी।

> प्रदेश सरकार अपने वादों पर अडिग है और हर वादा पूरा किया जाएगा। इस समय हालात ऐसे बने हैं कि मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित होने के कारण आइसोलेट हैं। जैसे ही वह स्वस्थ हो कर शिमला लौटेंगे, पहले मंत्रिमंडल गठन का कार्य पूरा होगा। उसके बाद सरकार ओपीएस और एक लाख नौकरियां देने के संबंध में निर्णय लेगी। - नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार

अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

कांग्रेस के प्रयागराज प्रांत के अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ पुलिस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ है।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोमवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय राबर्ट्सगंज आए थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अमेठी में स्मृति इरानी आती हैं और लटके-झटके देकर चली जाती हैं। वहां की जनता को उनके सांसद होने का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अमेठी से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। उनकी टिप्पणी के बाद जिले की राजनीति गरमा गई। मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचीं और अजय राय के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का मुकदमा दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष पुष्पा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के बारे में कांग्रेस नेता की टिप्पणी निंदनीय हैं। ऐसे लोग समाज में क्यों खुले घूम रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्र ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग आयोग ने भी दिया नोटिस : राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता के खिलाफ उनकी अभद्र टिप्पणी पर का संज्ञान लेते हुए राय को नोटिस भेजकर 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक पेश होने को कहा।

अजय राय। फाइल

स्मृति इरानी के खिलाफ कहे थे अपशब्द, भाजपा महिला मोर्चा ने की शिकायत

हंगामे की भेंट चढ़ा गुजरात विधानसभा का पहला सत्र

राज्य ब्यूरो, गांधीनगर

गुजरात की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए विधायक शंकर चौधरी को सर्वसम्ति से चुन लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सदन में अध्यक्ष पद के लिए चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय न देने पर कांग्रेस ने हंगामा किया तथा सदन से वाकआउट किया। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र मंगलवार को बुलाया गया। इसमें शंकर चौधरी को सर्वसम्ति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संसदीय मामलों के मंत्री ऋषीकेश पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शैलेष परमार चौधरी को अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गये। चौधरी बनास डेरी के चेयरमैन हैं। विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय न देना नियमों के विरुद्ध है। एक दिन का सत्र बुलाना संसदीय प्रणाली के विपरीत है।

▶ शंकर चौधरी सर्वसम्मति से चुने गए विधानसभा अध्यक्ष

सदन के युवा चेहरे : सदन में युवा चेहरे हर्ष संघवी, जिग्नेशा मेवाणी, रीवाबा जडेजा ने सबका ध्यान आकर्षित किया। हर्ष संघवी को इस बार भी गृह राज्य मंत्री बनाने के साथ कई मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। रीवाबा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं तथा पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। जबकि जिग्नेशा दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। उधर, पहली बार विधायक बने हार्दिक पटेल ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया। भाजपा के दूसरे विधायक एवं ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर एक लंबे अंतराल के बाद दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस में आपसी खींचतान के चलते नेता विपक्ष के नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। विगत रविवार को हुई में नेता विपक्ष के नाम पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे पर छोड़ दिया गया।

मनोज मुंतशिर ने राहुल पर साधा निशाना, कहा- विदेशी मां का बेटा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता

राज्य ब्यूरो, भोपाल

चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने निशाना साधा। राहुल का नाम लिए बिना कहा कि चाणक्य ने भी लिखा है कि विदेशी मां से पैदा हुआ बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। यह डीएनए की समस्या है। उन्होंने यह बयान सोमवार देर रात विक्रम शोध पीठ उज्जैन और एक निजी विश्वविद्यालय के संयुक्त कार्यक्रम में दिया। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह चारण-भाट की भाषा है। मुंतशिर ने राज्य के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की।

शोध पीठ के राष्ट्रीय विमर्श में आए मुंतशिर ने कहा कि अभी हमने चीन को भगाया। हमें दुख होता है, जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता कहता है कि हमारे देश के सैनिक चीन के सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग कोई कैसे कर सकता है, पर मैं उसे क्या दोष दूं, मैंने चाणक्य को पढ़ा है। मुंतशिर ने कहा कि भारत वर्ष में अनेक शूरवीर हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम 'जो जीता वही सिकंदर' कहावत क्यों कहते हैं? हम जानते हैं कि सिकंदर विदेशी आक्रांता था। हमें यही पढ़ाया गया कि सिकंदर विश्व विजय करते हुए भारत आया और पोरस को हराकर यहां से गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसे यहां से खदेड़ दिया गया। हमें जो जीता वही सिकंदर नहीं, बल्कि 'जो जीता वही विक्रमादित्य' बोलना चाहिए। उधर, युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने ट्वीट किया कि मनोज मुंतशिर जी, कलाकार हैं, कलाकार हो रहिए, भाजपा के एजेंट मत बनिए।

▶ कांग्रेस ने कहा - कलाकार हैं, कलाकार ही रहिए, भाजपा के एजेंट मत बनिए

मनोज मुंतशिर। नईदुनिया

बिहार में निकाय चुनाव में बहू से हार गई भाजपा सांसद की पत्नी

जागरण टीम, पटना

बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का परिणाम रोचक रहा है। वैशाली जिला में हाजीपुर के वार्ड एक से रमा निषाद पार्षद का चुनाव हार गई हैं। उन्हें चचेरी पुत्रवधू ज्योत्सना ने हराया, जो एमबीए डिग्रीधारी हैं। हाजीपुर नगर पालिका की सभापति व उप सभा पति रह चुकी रमा मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू हैं। उधर सारण के दिघवारा नगर पंचायत चुनाव में वार्ड सात से श्रम संसधन मंत्री सुरेंद्र राम की मां कलावती देवी को मुनेश्वर कुमार से हार का सामना करना पड़ा। सरकार में सुरेंद्र राम राजद कोटे के प्रतिनिधि हैं। भीजपुर के पीरो नगर परिषद में मुख्य पार्षद पद पर जदयू के प्रदेश महासचिव मनोज उपाध्याय की पत्नी किरण देवी चुनाव जीत गई हैं।

सिवान जिला में महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड छह में निवर्तमान वार्ड पार्षद रंजू देवी और प्रत्याशी संगीता को बराबर वोट मिले। इसके बाद वहां टास से रंजू देवी की जीत हुई। भीजपुर के बिहिया नगर पंचायत में एक ही परिवार से पति-पत्नी और भाभी की जीत हुई है। विजय कुमार गुप्ता उप मुख्य पार्षद बने हैं तो पत्नी पूजा देवी व चाची अंजू देवी वार्ड पार्षद। दोनों के वार्ड अगल-बगल (10 और 11) हैं। उधर बक्सर जिला के चौसा में 21 वर्षीया छात्रा अंजू कुमारी वार्ड सदस्य बनी हैं। गोपालगंज की मीरगंज नगर पंचायत में सास और बहू दोनों एक साथ वार्ड पार्षद बनी हैं।

28 को दूसरे चरण का मतदान : बिहार के 156 नगर निकायों में रविवार को पहले चरण का मतदान हुआ था। पहले चरण में 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत थीं। पहले चरण में 51 महिलाएं मुख्य पार्षद तथा इतनी ही संख्या में उप मुख्य पार्षद चुनी गईं।

▶ राजद कोटे के मंत्री सुरेंद्र राम की मां कलावती देवी को मिली पराजय

रमा निषाद (फाइल फोटो) जागरण आर्काइव

▶ सिवान जिला में महाराजगंज नगर पंचायत चुनाव में मिले बराबर वोट

रमा निषाद की चचेरी पुत्रवधू ज्योत्सना जागरण

भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही व केंद्र के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही : बघेल

राज्य ब्यूरो, रायपुर : शाह रुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान में भगवा रंग के कपड़ों पर उठे विवाद ने छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म का विरोध कर रहे लोगों पर प्रश्न उठाया तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने उन्हें राक्षस कह दिया। इसके जवाब में मंगलवार को भूपेश बघेल केंद्र सरकार के विरुद्ध हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के विरुद्ध बोलो तो धर्मद्रोही, केंद्र के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही और इनके खिलाफ बोलो तो राक्षस। इनके पास सार्टिफिकेट की फैक्ट्री है, जो ये बांटते सबको रहते हैं।

ज्ञात हो कि फिल्म पठान में भगवा रंग के उपयोग के संबंध में पूछ गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि भगवा रंग तो त्याग और बलिदान का रंग है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले जो भगवा पहनकर घूम रहे हैं। कोई यह बताए कि उन्होंने कौन सा त्याग किया है। शाह रुख खान, दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है।

****

भारत जोड़ो यात्रा : राजस्थान में 16 दिन में तय हुआ 521 किलोमीटर का सफर

जागरण संवाददाता, जयपुर

▶ अंतिम दिन गहलोत के साथ कन्नी भी पैदल चले

▶ आज हरियाणा में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा

भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में 16 दिन में 521 किलोमीटर की यात्रा तय की है। चार दिसंबर को यात्रा मध्य प्रदेश से झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में पहुंची थी। मंगलवार को राजस्थान में यात्रा के अंतिम दिन अलवर में किसान, महिलाएं और बच्चे राहुल के साथ पैदल चले। खिलाड़ियों के साथ राहुल ने खेलों पर चर्चा की।

अंतिम दिन यात्रा में काफी भीड़ नजर आई। यात्रा बुधवार को हरियाणा में प्रवेश करेगी। मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के साथ राजस्थान सरकार के करीब एक दर्जन मंत्री और कांग्रेस के विधायक यात्रा में शामिल हुए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरविंद मायाराम भी राहुल के साथ चले। यात्रा का स्वगत करने पहुंचे स्थानीय कलाकारों से राहुल ने संवाद किया। मंगलवार को यात्रा अलवर के कटिघारी पार्क से प्रारंभ होकर रामगढ़ पहुंची। रामगढ़ के बिजवा गांव में यात्रा का विराम हुआ। अब बुधवार को यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी।

राहुल ने ट्वीट किया : राहुल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा एलान है। अब यहां केंद्र सरकार की कीमतों के आधे से भी कम दाम में सिलेंडर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। दरअसल, एक दिन पहले सीएम गहलोत ने जरूरतमंदों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी। वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार ऐसा करने से राज्य सरकार पर 3294 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

हर महीने यात्रा करेंगे मंत्री

राहुल के निर्देश पर राजस्थान सरकार के मंत्री अब हर महीने 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। पहले 26 जनवरी को अपने प्रभार वाले जिलों में पदयात्रा करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने के बाद मंत्री स्थानीय विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों के साथ पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के दौरान मंत्री आम लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण करेंगे।